पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2020 की चुनाव याचिका संख्या 5

= =

गजानंद शाही स्वर्गीय हरगोविंद प्रसाद सिंह के पुत्र, निवासी हाउस नंबर 41, वार्ड नंबर 28, डाकबंगलो रोड (हरगोविंद भवन), पुलिस स्टेशन–पटना कोटवाली, पोस्ट–जी. पी. ओ., जिला–पटना।

..................याचिकाकर्ता/गण

बनाम

सुदर्शन कुमार स्वर्गीय संजय कुमार सिंह के पुत्र, ग्राम और चौकी–हथियावां, पुलिस स्टेशन–शेखपुरा, जिला–शेखपुरा के निवासी हैं।

...........प्रतिवादी

= =

उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	भूषण कुमार मंगलम
प्रत्यर्थी/ओं के लिएः	:	अंसुल, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री माधव राज

= =

चुनावी याचिका – एकमात्र प्रतिवादी, जिसे बिहार विधान सभा का सदस्य घोषित किया गया है, के चुनाव को रद्द करने के लिए दाखिल की गई।

चुनाव को रद्द करने का आधार, जैसा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है, वह है एकमात्र प्रतिवादी के नामांकन पत्र को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अनुचित रूप से स्वीकार करना और मतगणना में गड़बड़ी।

निष्कर्ष – रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन पत्र का अनुचित स्वीकार किया जाना, चुनाव को अमान्य घोषित करने के आधारों में से एक है। यदि रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन पत्र को अनुचित रूप से स्वीकार करता है, तो जीते हुए प्रत्याशी का चुनाव अमान्य घोषित किया जा सकता है। परंतु, धारा 100(1)(d)(i) के स्पष्ट अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि नामांकन पत्र के अनुचित स्वीकृति के कारण चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए यह आवश्यक है कि इसका चुनाव के परिणाम पर भौतिक प्रभाव पड़ा हो। (पैरा 34)

सिर्फ इसलिए कि नामांकन पत्र भरने या हलफनामा प्रस्तुत करने में कुछ त्रुटियाँ हुई हैं, चुनाव को अमान्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये त्रुटियाँ इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं कि इनका चुनाव परिणाम पर भौतिक प्रभाव पड़ा हो। (पैरा 36)

याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि प्रतिवादी ने अपने नामांकन पत्र में कोई विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई थी। केवल कुछ अनियमितताओं के आधार पर चुनाव को अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि चुनाव याचिकाकर्ता यह सिद्ध करने में असफल रहा कि इन अनियमितताओं का चुनाव परिणाम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। (पैरा 38)

यदि चुनाव याचिकाकर्ता केवल जीते हुए प्रत्याशी के चुनाव को अमान्य घोषित करने की प्रार्थना करता है और स्वयं को निर्वाचित घोषित करने का दावा नहीं करता, तो ऐसे मामले में जीते हुए प्रत्याशी आवश्यक पक्षकार होते हैं। (पैरा 40)

चुनाव याचिकाकर्ता ने उस अधिकारी का नाम और पद नहीं बताया, जिसने उसे यह जानकारी दी कि डाक मतपत्रों की गिनती ईवीएम से डाले गए मतों की गिनती के बाद हुई थी। चुनाव याचिकाकर्ता ने उस अधिकारी को गवाही के लिए भी तलब नहीं किया। (पैरा 43)

फॉर्म–20 (अंतिम परिणाम पत्र) में दर्ज प्रविष्टियों के क्रम से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि डाक मतपत्रों की गिनती ईवीएम से डाले गए मतों की गिनती के बाद की गई थी। फॉर्म–20 में प्रविष्टियाँ तभी की जाती हैं जब मतगणना पूरी हो चुकी होती है। (पैरा 44)

फॉर्म–20 के प्रारूप का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि सबसे पहले ईवीएम से डाले गए मतों की प्रविष्टि की गई है और उसके बाद डाक मतपत्रों से प्राप्त मतों की प्रविष्टि की गई है। अतः, चुनाव याचिकाकर्ता यह साबित करने में असफल रहा कि डाक मतपत्रों की गिनती ईवीएम मतों की गिनती के बाद हुई थी। (पैरा 45)

चुनावी याचिका खारिज की जाती है। (पैरा 47)

पटना उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेश

= =

.कोरमः माननीय न्यायधीश न्युनित कुमार पांडे
सीएवी निर्णय
तिथि –07.01.2025

1. मैंने पहले ही याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री एस. बी. के. मंगलम के साथ–साथ विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अंसुल को सुना है, जिन्हें एकमात्र प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील श्री माधव राज द्वारा सहायता प्रदान की गई है।

2. याचिकाकर्ता ने यह चुनाव याचिका एकमात्र प्रतिवादी के चुनाव को रद्द करने के लिए दायर की है, जिसे 170, बरबीघा विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा का सदस्य घोषित किया गया है। चुनाव 28.10.2020 पर आयोजित किया गया था और परिणाम 10.11.2020 पर घोषित किया गया था। जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया है, चुनाव को रद्द करने का आधार निर्वाचन अधिकारी द्वारा एकमात्र प्रतिवादी के नामांकन पत्र की अनुचित स्वीकृति है।

3. याचिका में दिए गए कथन के अनुसार, याचिकाकर्ता और एकमात्र प्रतिवादी सहित कुल 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। जांच की तारीख यानी एक स्वतंत्रता उम्मीदवार श्री अजय कुमार का नामांकन पत्र अधूरा पाया गया था और इसे निर्वाचन अधिकारी ने खारिज कर दिया था, लेकिन साथ ही निर्वाचन अधिकारी ने एकमात्र प्रतिवादी का नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया था जो भी अधूरा था। फॉर्म–26 में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष एकमात्र प्रतिवादी द्वारा दायर हलफनामे के प्रारूप में सही और भौतिक जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने अपने नामांकन पत्र का भाग–3 ए नहीं भरा था और इस आधार पर उनका नामांकन पत्र अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन इसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुचित तरीके से स्वीकार कर लिया गया था। चुनाव की तारीख को, 1,19,144 मतदाताओं ने 223 मतदान केंद्रों पर अपने चुनावी अधिकारों का प्रयोग किया था, जबकि निर्वाचन अधिकारी को 1113 डाक बैले पेपर प्राप्त हुए थे। एकमात्र उत्तरदाता को निर्वाचित घोषित किया गया था क्योंकि उन्हें डाक मतपत्रों सहित 39878 मत प्राप्त हुए थे, जबकि याचिकाकर्ता को डाक मतपत्रों सहित 39765 मत प्राप्त हुए थे।

4. याचिका में आगे यह कहा गया है कि एकमात्र प्रतिवादी ने दो सेटों (Ext.1 और 1 (ii)) में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। नामांकन पत्र में, उन्होंने दो सेटों में फॉर्म–26 में एक हलफनामा भी दाखिल किया था, जिस पर उनके द्वारा नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे। हलफनामे के इन दो सेटों को एक्स्ट के रूप में चिह्नित किया गया है। 2 और एक्स. 2 ए. उन्होंने भारत के चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना नामांकन पत्र भी अपलोड किया। याचिकाकर्ता ने अपने नामांकन पत्र की प्रमाणित प्रति और प्रपत्र में शपथ पत्र प्राप्त किया –26. नामांकन पत्रों

के सभी दो सेट और फॉर्म–26 में शपथ पत्र कई दुर्बलताओं से पीड़ित थे। यह आगे उल्लेख किया गया है कि एकमात्र प्रतिवादी ने नामांकन पत्र के दोनों भागों यानी भाग–1 और भाग–2 को भरा था, जबकि उसे केवल भाग–1 को भरना था, जैसा कि भाग–3 से स्पष्ट है। एकमात्र उत्तरदाता जनता दल (यूनाइटेड) राजनीतिक दल का उम्मीदवार था और एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार को केवल भाग–1 भरना था, न कि भाग –2. नामांकन पत्र के पैराग्राफ–3 में दिए गए निर्देश के अनुसार भाग–2 को पार किया गया होगा। चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा एकमात्र प्रत्यर्थी के नामांकन पत्र में इंगित की गई दूसरी कमजोरी यह है कि उसने नामांकन पत्र के भाग–3 ए में प्रासंगिक विवरण नहीं दिया था, जिसमें एक उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से यह घोषित करने की आवश्यकता होती है कि क्या उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (इसके बाद 'अधिनियम, 1951' के रूप में संदर्भित) की धारा 8 (1) और धारा 8 (2) के तहत किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, या किसी अन्य पटना उच्च न्यायालय के ई. पी. 2020 की संख्या 5 के लिए। दो साल से अधिक के अपराध। उक्त भाग–3 ए का पैरा–1 खाली है और इस एकमात्र चूक पर, एकमात्र प्रतिवादी का नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

5. याचिका में आगे कहा गया है कि फॉर्म–26 के पैराग्राफ 4 को भरने का निर्देश उस पैराग्राफ के फुटनोट पर दिया गया था। एक उम्मीदवार के लिए पैरा–4 में अपनी स्थायी खाता संख्या (संक्षेप में 'पैन') का उल्लेख करना अनिवार्य है, और यदि उसके पास कोई पैन नहीं है, तो उसे स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि उसे पैन आवंटित नहीं किया गया था। हालांकि एकमात्र प्रतिवादी ने अपने पैन और अपनी पत्नी के पैन का उल्लेख किया है, लेकिन उसने निर्धारित प्रपत्र में निहित निर्देशों के अनुसार पैरा–4 के अन्य कॉलम के संबंध में जानकारी नहीं भरी थी। एकमात्र प्रत्यर्थी ने अपने शपथ पत्र के पैरा–4 में प्रासंगिक अनिवार्य जानकारी को छिपा दिया था और इसलिए, उनका नामांकन पत्र अस्वीकार किए जाने के योग्य था। इसी तरह, शपथ पत्र के पैरा–5 और 6 को खाली छोड़ दिया गया था। प्रत्यर्थी ने अपने हलफनामे में यह घोषणा नहीं की है कि या तो उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, या उसके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। इसी तरह, एकमात्र प्रतिवादी ने भी शपथ पत्र के पैराग्राफ 6 में उल्लेख नहीं किया कि क्या उसे दोषी ठहराया गया है या उसे किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। याचिका में आगे यह उल्लेख किया गया है कि हलफनामे के पैरा–7 (ए) के अनुसार, 2020 की पटना उच्च न्यायालय ई. पी. संख्या 5 डी. उम्मीदवार को अपनी संपत्ति (चल और अचल) घोषित करनी होगी। उसकी बीमा नीतियों के संबंध में उक्त पैराग्राफ में निहित निर्देशों के अनुसार, पैराग्राफ नंबर के उप–पैराग्राफ नंबर (iv) में उल्लिखित उसके जीवनसाथी के कॉलम में। 7, एकमात्र उत्तरदाता ने केवल रु। 2,00,000–, ओरिएंटल बैंक, बसंत कुंज, दिल्ली, लेकिन नीतियों की प्रकृति क्या है, हलफनामा मौन है और उक्त

हलफनामे के अगले पृष्ठ पर उन्होंने उप–अनुच्छेद संख्या के सभी स्तंभों में 'शून्य' यानी '0' का उल्लेख किया है। ((iv) अनुच्छेद सं। 7 (ए)।

6. यह भी कहा गया है कि एकमात्र प्रतिवादी के मोटर वाहनों का विवरण भी शपथ पत्र में अधूरा था क्योंकि खरीद का वर्ष, और खरीद की राशि का उल्लेख उसके शपथ पत्र में नहीं किया गया है। इसी तरह, पैराग्राफ नं. में एकमात्र प्रतिवादी द्वारा दी गई जानकारी। प्रपत्र–26 में उनके शपथ पत्र का 7 (बी) निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र भरने की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है और इसलिए, एकमात्र प्रतिवादी का नामांकन इस आधार पर अस्वीकार किए जाने के लिए उपयुक्त था। एक उम्मीदवार को अपने शपथ पत्र के पैराग्राफ 7 (बी) (1) में अपनी कृषि भूमि के स्थान और सर्वेक्षण संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है, लेकिन सर्वेक्षण कॉलम में, प्रतिवादी ने केवल भूमि के क्षेत्र का उल्लेख किया है जो निर्धारित प्रारूप/प्रपत्र के अनुसार नहीं है। इसी तरह, आवासीय इमारतें, जैसा कि अनुच्छेद संख्या में उल्लेख किया गया है। 7 बी (iv), प्रतिवादी ने केवल दो फ्लैटों का उल्लेख किया है, शेखपुरा में एक घर, पटना और कोलकाता में एक फ्लैट और पटना में एक पारिवारिक घर। यह भी आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन अधिकारी ने दबाव में, एकमात्र प्रतिवादी के नामांकन पत्र को अनुचित तरीके से स्वीकार करने के बाद, मतों की गिनती में भी घोर अवैधता की थी। चुनाव आचरण नियम 1961 के नियम 54 ए के अनुसार (जिसे इसके बाद 'नियम, 1961' के रूप में संदर्भित किया जाएगा), निर्वाचन अधिकारी को अनिवार्य रूप से पहले डाक मतपत्रों की गिनती करनी होती है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों (ई. वी. एम. एस.) के माध्यम से मतों की गिनती शुरू होनी चाहिए, लेकिन इस नियम का उल्लंघन करते हुए, डाक मतपत्रों की गिनती ई. वी. एम. एस. के माध्यम से डाले गए मतपत्रों के बाद की गई थी और यह तथ्य फॉर्म–20 से स्पष्ट है जिसमें अंतिम परिणाम पत्रक निर्वाचन अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। डाक मतपत्रों के माध्यम से मतों के विवरण का उल्लेख ई. वी. एम. के माध्यम से मतों के बाद फॉर्म 20 में किया गया है, जो दर्शाता है कि ई. वी. एम. के माध्यम से डाले गए मतों की पहले गिनती की गई और उसके बाद डाक मतपत्रों की गिनती की गई।

7. एकमात्र प्रतिवादी ने चुनाव याचिका में किए गए कथनों को नकारते हुए अपना लिखित बयान दायर किया है। लिखित बयान में यह उल्लेख किया गया है कि चुनाव याचिका 2020 की पटना उच्च न्यायालय ई. पी. संख्या 5 होनी चाहिए। आवश्यक पक्षों के जवाब न देने के आधार पर बर्खास्त किया जाए क्योंकि निर्वाचन अधिकारी जिसके खिलाफ एकमात्र प्रतिवादी के नामांकन पत्र को अनुचित तरीके से स्वीकार करने का आरोप है, को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया है। चुनाव याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई मामला नहीं उठाया है कि एकमात्र प्रतिवादी की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है और न ही याचिकाकर्ता का

मामला यह है कि एकमात्र प्रतिवादी के पास उनके नामांकन पत्र या फॉर्म–26 में दिखाई गई संपत्ति के अलावा कोई अन्य चल या अचल संपत्ति है। नामांकन पत्र या फॉर्म–26 में और क्या विवरणों का उल्लेख किया जाना बाकी है, यह चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। कानून के अनुसार, नामांकन पत्र को निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी भी दोष के आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा जो महत्वपूर्ण चरित्र का नहीं है। नामांकन पत्र में कोई भी त्रुटियां या चूक, यदि यह एक महत्वपूर्ण चरित्र की नहीं है, तो कोई मायने नहीं रखती है।

8. लिखित बयान में आगे यह अनुरोध किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, एक उम्मीदवार को स्पष्ट रूप से "शून्य" या "लागू नहीं" या "ज्ञात नहीं" आदि के रूप में चिह्नित करने के लिए न्यूनतम प्रयास करना चाहिए। यही कारण था कि एकमात्र प्रतिवादी ने उन सभी स्थानों पर 'शून्य' यानी '0' लिखा था जहां उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। यह भी अनुरोध किया गया है कि जहां तक डाक मतपत्र की गिनती के आरोप की बात है, पटना उच्च न्यायालय ई. पी. संख्या 5,2020, डी. टी.ई. वी. एम. के माध्यम से मतों की गिनती के बाद मतपत्रों का संबंध है, मतों के प्रकाशन के क्रम से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि डाक मतपत्रों की गिनती ई. वी. एम. के माध्यम से डाले गए मतपत्रों के बाद की गई थी।

9. लिखित बयान में यह भी उल्लेख किया गया है कि एकमात्र प्रतिवादी ने भाग–1 और भाग–2 दोनों को भरा था, लेकिन याचिकाकर्ता का ऐसा कोई मामला नहीं है कि नामांकन पत्र के दोनों भागों को भरने के कारण कोई गलत जानकारी दी गई थी या कुछ भ्रामक था। वास्तव में, एकमात्र प्रतिवादी का नामांकन पत्र दाखिल करते समय कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और उसने स्पष्ट रूप से मामलों के खिलाफ "शून्य" यानी "0" लिखा था, जिसका अर्थ स्पष्ट रूप से यह था कि उसके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है या उसे किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। "शून्य" का शाब्दिक अर्थ कुछ भी नहीं है और यह किसी भी मामले की अनुपस्थिति का संकेत देता है और इसके विपरीत कुछ भी व्यक्त नहीं किया जा सकता है। फॉर्म–26 में उनके हलफनामे में आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित कॉलम के साथ भी यही स्थिति है। एकमात्र प्रतिवादी ने फॉर्म–26 में अपने और अपनी पत्नी के पैन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। उन्होंने एकमात्र प्रतिवादी के बेटों आर्यन और आदिर कुमार के पैन नहीं भरे, क्योंकि वे नाबालिग थे और उन्हें पैन आवंटित नहीं किए गए थे और यही कारण था कि पटना उच्च न्यायालय के ई. पी. संख्या 5 के कॉलम के सामने "शून्य" शब्द का उल्लेख किया गया था। आर्यन और आदिर कुमार के पैन। अभियोग में यह कथन कि कॉलम 7 (iv) में संपत्तियों का विवरण नहीं दिया गया था, एकमात्र प्रतिवादी द्वारा भी अस्वीकार कर दिया गया था। यह उल्लेख किया गया है कि उनकी चल और अचल संपत्तियों का विवरण फॉर्म–26 के

पैरा–7 (iv) में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है और अगले पृष्ठ पर रिक्त स्थानों को "शून्य" से भरा गया था जो कोई गलत/विपरीत अर्थ नहीं बता सकता है और अधिनियम, 1951 की धारा 36 (4) द्वारा प्रभावित नहीं होगा।

10. अंत में, लिखित बयान में यह अनुरोध किया गया है कि जहां तक एकमात्र प्रतिवादी के मोटर वाहनों, भूमि और घरों का संबंध है, उन्होंने पूरे आवश्यक विवरण प्रस्तुत किए हैं और यह चुनाव याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि एकमात्र प्रतिवादी के पास कोई अन्य मोटर वाहन, भूमि संपत्ति या घर हैं जिन्हें नामांकन पत्र के साथ संलग्न फॉर्म–26 में घोषित किया गया है। अंत में, एकमात्र प्रतिवादी ने चुनाव याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया क्योंकि यह निराधार है।

11. पक्षकारों की दलीलों के आधार पर, निम्नलिखित मुद्दों को निर्णय के लिए तैयार किया गया हैः .

(1) क्या एकमात्र प्रत्यर्थी के नामांकन पत्र को परिवीक्षा के समय निर्वाचन अधिकारी द्वारा शिकायत में उल्लिखित दुर्बलताओं के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था?

(2) क्या एकमात्र प्रत्यर्थी के चुनाव को अलग रखा जाना चाहिए?

12. इन दोनों मुद्दों को निर्णय के लिए एक साथ लिया जाता है।

13. चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एकमात्र प्रतिवादी द्वारा दायर नामांकन पत्र के दो सेटों की प्रमाणित प्रतियां हैं जिन्हें क्रमशः Ext.1 और 1 (ii) के रूप में चिह्नित किया गया है। नामांकन पत्र के साथ संलग्न फॉर्म–26 में शपथ पत्र के दो सेटों की प्रमाणित प्रतियों को Ext.2 और अतिरिक्त के रूप में चिह्नित किया गया है। 2 (ए)।

14. जहाँ तक मौखिक साक्ष्यों का संबंध है, याचिकाकर्ता की ओर से एकमात्र गवाह, याचिकाकर्ता स्वयं (पी. डब्ल्यू. 1) से पूछताछ की गई थी। जहाँ तक एकमात्र प्रत्यर्थी का संबंध है, उसकी ओर से तीन गवाहों से पूछताछ की गई, जिसमें वह भी शामिल था।

15. आर. डब्ल्यू. 1 स्वयं एकमात्र उत्तरदाता है। आर. डब्ल्यू. 2 एक राजेश कुमार है, जो एकमात्र उत्तरदाता का निजी सहायक है और वह एकमात्र उत्तरदाता के लिए गिनती एजेंटों में से एक था और आर. डब्ल्यू. 3 मनोज प्रसाद है, जो एकमात्र उत्तरदाता के गिनती एजेंटों में से एक है।

16. पी. डब्ल्यू. 1, जो स्वयं याचिकाकर्ता हैं, ने अपनी याचिका में उल्लिखित अपने कथन को दोहराया है। उन्होंने अपदस्थ कर दिया है कि निर्वाचित उम्मीदवार श्री सुदर्शन कुमार के चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि उन्होंने नामांकन पत्र के भाग 3 ए को भरना छोड़ दिया है। चुनाव यह है कि डाक मतपत्रों की गिनती पहले की जानी चाहिए थी, जबकि उनकी गिनती अंतिम में की जानी चाहिए थी। उन्होंने नामांकन पत्र के साथ फॉर्म–26 में एकमात्र प्रतिवादी द्वारा दायर हलफनामे में कमियों के आधार पर एकमात्र प्रतिवादी के चुनाव को भी चुनौती दी है। इस गवाह के कहने पर, नामांकन पत्र और प्रपत्र–26 की प्रमाणित प्रतियों को प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित किया गया था। इस गवाह ने गवाही दी है कि हालांकि प्रतिवादी नहीं। 1 फॉर्म–26 में आपराधिक मामलों को कॉलम संख्या में '0' के रूप में दिखाया गया है। 5, लेकिन उन्होंने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया था कि उनके खिलाफ कोई मामला लंबित है या नहीं, जैसा कि कॉलम संख्या में कहा गया है। 5(i) और 5 (ii)। कॉलम नं. के संबंध में भी यही स्थिति है। 6 फॉर्म–26। प्रत्यर्थी ने अपने और अपनी पत्नी के लिए फॉर्म–26, कॉलम 7 (ए) (ii) में अपने बैंक खाते की संख्या का उल्लेख नहीं किया है। एकमात्र प्रत्यर्थी और उसकी पत्नी से संबंधित फॉर्म–26 के कॉलम 7 (ए) (iv) में वाहन की खरीद के वर्ष और उसकी कीमत का उल्लेख नहीं किया गया है। कॉलम 7 (बी) (आई) में, हालांकि भूमि के क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, लेकिन स्थान और भूखंड संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। इसी तरह, फॉर्म–26 के पैराग्राफ 7 (बी) (iv) में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और फ्लैटों का स्थान गायब है। पैराग्राफ नं. के उप कॉलम में। 7(बी) (iv), उम्मीदवार को यह खुलासा करना आवश्यक है कि क्या उसमें उल्लिखित संपत्तियां विरासत में मिली हैं या स्वयं–पटना उच्च न्यायालय ई. पी. संख्या 5 2020 डी. अर्जित किया। स्तम्भ सकारात्मक रूप में भरा गया है। हालांकि, अगले दो कॉलम में, यह उल्लेख किया गया है कि कॉलम 7 (बी) (iv) में प्रकट किए गए फ्लैट विवरण एकमात्र प्रतिवादी की खरीदी गई संपत्ति है। यह उत्तरदाता द्वारा अपने नामांकन पत्र के साथ जमा किए गए फॉर्म–26 के दोनों सेटों में स्थिति है। इस गवाह ने यह भी बयान दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से डाले गए मतों की गिनती के बाद डाक मतपत्रों की गिनती की गई थी। अंतिम परिणाम पत्रक फॉर्म 20 में, सबसे पहले, ई. वी. एम. के माध्यम से मतों का विवरण दर्ज किया गया है और बाद में डाक मतपत्र के माध्यम से डाले गए मतों को दर्ज किया गया है। अपनी जिरह के दौरान, इस गवाह ने गवाही दी कि वह एकमात्र प्रतिवादी के दो नाबालिग बच्चों के पैन कार्ड नंबरों का उल्लेख नहीं करने के कारण से अवगत नहीं था। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि इन नाबालिग बच्चों को पैन कार्ड नहीं दिए गए थे। इस गवाह ने आगे कहा है कि वोटों की गिनती में लगे अधिकारी ने उन्हें बताया कि डाक मतपत्रों की गिनती ई. वी. एम. के माध्यम से डाले गए वोटों की गिनती के बाद की गई थी। उन्होंने यह भी बयान दिया है कि उन्हें एकमात्र प्रतिवादी के खिलाफ लंबित किसी भी आपराधिक

मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में, कॉलम संख्या में एकमात्र प्रतिवादी द्वारा कोई विशिष्ट सामग्री नहीं छिपाई गई थी। 3 फॉर्म का ए।

17. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, एकमात्र प्रतिवादी की ओर से तीन गवाहों से पूछताछ की गई है।

18. आर. डब्ल्यू. 1 एकमात्र प्रतिवादी श्री सुदर्शन कुमार स्वयं हैं। उन्होंने पदच्युत कर दिया कि उन्होंने जनता दल (यूनाइटेड) राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव जीता। एक उम्मीदवार एक वकील की सहायता से अपना नामांकन पत्र भरता है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने नामांकन पत्र में आपराधिक पृष्ठभूमि के कॉलम को "शून्य" के रूप में भरा क्योंकि उनके खिलाफ कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी। उनके दो बेटे हैं और उनके दोनों बेटों के पास नामांकन पत्र दाखिल करने के समय पैन कार्ड नहीं था और यही कारण था कि चुनाव याचिका में उनके पैन कार्ड नंबर का उल्लेख नहीं किया गया था। प्रमाण पत्र संग्रह के समय, किसी ने भी उपयुक्त अधिकारियों के समक्ष चुनाव में किसी भी कदाचार की शिकायत नहीं की थी। मतों की गिनती के समय उनके गिनती एजेंट मनोज कुमार (आर. डब्ल्यू. 3), राजेश कुमार (आर. डब्ल्यू. 2), दिवाकर कुमार और धीरज कुमार मौजूद थे।

अपनी जिरह में, इस गवाह ने कहा है कि वह एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, जद (यू) का उम्मीदवार था। उनके द्वारा दाखिल किए गए नामांकन पत्रों को पहले ही एक्सट के रूप में चिह्नित किया जा चुका है। 1 और 1 (ii) और शपथ पत्र, फॉर्म–26 को निकास के रूप में चिह्नित किया गया है। 2 और 2 (ए)।शाम 6 बजे के बाद और गिनती स्थल पर उनके पहुंचने से पहले, गिनती समाप्त हो गई थी। उन्होंने अपनी जिरह के दौरान कहा कि राजेश कुमार (आर. डब्ल्यू. 2) ने उन्हें बताया कि डाक मतपत्रों की गिनती पहले की गई थी। उन्होंने ब्रजेश कुमार, धीरज कुमार और मनोज कुमार को अपने गिनती एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। उन्हें अपने गिनती एजेंट का नाम याद नहीं था, जिन्हें मेज पर प्रतिनियुक्त किया गया था, जहां डाक मतपत्रों की गिनती की गई थी, वे यह नहीं बता सके कि कितने डाक मतपत्र खारिज किए गए थे।

19. आर. डब्ल्यू. 2 राजेश कुमार एकमात्र प्रतिवादी के निजी सहायक हैं। उन्होंने कहा है कि नामांकन पत्रों के हलफनामे में, आपराधिक पृष्ठभूमि के कॉलम में, एकमात्र प्रतिवादी ने 'शून्य' का उल्लेख किया है। नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख तक उनके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं था। परिणाम की घोषणा के समय भी, चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई थी।

जिरह के दौरान, इन गवाहों ने गवाही दी कि वह नामांकन पत्र दाखिल करने के समय मौजूद थे, लेकिन उन्होंने नामांकन पत्र भरने में योगदान नहीं दिया। यह गवाह एकमात्र उत्तरदाता का गिनती एजेंट था।

20. आर. डब्ल्यू. 3 मनोज प्रसाद हैं, जो एकमात्र उत्तरदाता के गिनती एजेंट भी हैं। इस गवाह ने यह भी कहा है कि नामांकन पत्र दाखिल करने के समय, 2020 का कोई आपराधिक पटना उच्च न्यायालय ई. पी. संख्या 5 नहीं था। श्री सुदर्शन कुमार के खिलाफ पूर्व अभियोग। यह गवाह गिनती के समापन तक उस स्थान पर मौजूद था, जहां वोटों की गिनती चल रही थी। श्री गजानंद शाही (चुनाव याचिकाकर्ता) द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत करते हुए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था। गिनती के समय, पहले डाक मतपत्रों की गिनती की गई और उसके बाद, ई. वी. एम. के माध्यम से डाले गए मतों की गिनती की गई।

अपनी प्रतिपरीक्षा में, इस गवाह ने अपदस्थ किया है कि उसे टेबल नं. 1 और उनकी मेज पर डाक मतपत्रों की गिनती नहीं की गई। यह गवाह डाक मतपत्रों की कुल संख्या नहीं दे सका। इस गवाह ने परिणाम की घोषणा सुनी, लेकिन उसने परिणाम–पत्रक नहीं देखा।

21. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री एस. बी. के. मंगलम ने प्रस्तुत किया है कि भारत संघ बनाम के मामले में ***एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड ए. एन. आर.*** ने रिपोर्ट किया ***2002 (5) एस. सी. सी. 294,*** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिशा–निर्देश जारी किए। दिशानिर्देश जारी करने से पहले, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मतदाताओं के अपने उम्मीदवार को जानने के अधिकार को ध्यान में रखा गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार, एक मतदाता को अपने उम्मीदवार के बारे में जानने का अधिकार है। माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार 'जानने का अधिकार', 2020 के पटना उच्च न्यायालय ई. पी. संख्या 5 के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में निहित बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से व्युत्पन्न है। मतदाताओं को अपने उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि, चल और अचल संपत्तियों सहित उनकी संपत्ति और देनदारियों के साथ–साथ शैक्षिक योग्यता को जानने का अधिकार है। इस निर्णय के बाद, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में धारा 33–ए को जोड़ा गया, जिसे इसके बाद 'अधिनियम, 1951' के रूप में संदर्भित किया गया, जिसमें एक उम्मीदवार को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा करने की आवश्यकता होती है, जो एक लंबित मामले में दो साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है जिसमें एक सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा आरोप तैयार किया गया है। एक उम्मीदवार के लिए यह खुलासा करना भी अनिवार्य है कि क्या उसे उप–धारा (1) या उप–धारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपराध के अलावा

किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, या 'अधिनियम, 1951' की धारा 8 की उप–धारा (3) में शामिल किया गया है और क्या उसे एक वर्ष से अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई थी।

22. श्री मंगलम ने आगे कहा है कि यदि कोई उम्मीदवार नामांकन पत्र को ठीक से नहीं भरकर अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा करने में विफल रहता है, तो यह तथ्य को छिपाने के बराबर है और मतदाताओं के अपने उम्मीदवार को जानने के अधिकार का उल्लंघन है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है। यदि नामांकन पत्र या प्रपत्र–26, जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि का विवरण दिया गया है, अनुचित रूप से भरा गया है, तो मतदाता 2020 के पटना उच्च न्यायालय ई. पी. संख्या 5 के बारे में जानकारी के संबंध में द्विविभक्त स्थिति में हो सकते हैं।

चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार, और यदि यह द्विभाजन उम्मीदवार द्वारा स्वयं बनाया गया है, तो उसका चुनाव इस आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। उन्होंने पीपुल्स यूनियन फॉर के फैसले पर भी भरोसा किया। **सिविल लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) और ए. एन. आर. बनाम भारत संघ और ए. एन. आर., 2003 (4) एस. सी. सी. 399** में रिपोर्ट की गई, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हालांकि 'अधिनियम, 1951' की धारा 33–बी को अल्ट्रा वायरस घोषित किया, लेकिन साथ ही, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 33–ए पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष तथ्य को छुपाता है जिसे नामांकन पत्र या फॉर्म–26 में प्रकट करना अनिवार्य है, तो उसका चुनाव निर्धारित किया जा सकता है। उन्होंने मेरा ध्यान **मीरेम्बम पृथ्वीराज बनाम** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की ओर आकर्षित किया **पुखरम शरतचंद्र सिंह ने 2017 में रिपोर्ट किया (1) पी. एल. जे. आर. (एससी) 50** और उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक उम्मीदवार का चुनाव, जो मणिपुर विधानसभा चुनाव में सफल हुआ, केवल इस आधार पर निर्धारित किया गया था कि उसने अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में फॉर्म 26 में गलत जानकारी भरी थी। उस मामले में, उम्मीदवार ने अपने नामांकन पत्र में उल्लेख किया कि वह मैसूर विश्वविद्यालय से एमबीए (मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) थे। यह जानकारी झूठी पाई गई और इसी एकमात्र कारण से, उनका चुनाव माननीय मणिपुर उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी निर्धारित किया गया था। उनका आगे निवेदन है कि **किसान शंकर के मामले में कथोर बनाम अरुण दत्तात्रेय सावंत और अन्य, (2014) 14 में रिपोर्ट किए गए एस. सी. सी. 162,** विधान सभा के चुनाव में एक सफल उम्मीदवार का चुनाव माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंगला संख्या 866 के स्वामित्व का खुलासा न करने के साथ–साथ वाहन संख्या 866 का खुलासा न करने के लिए निर्धारित किया गया था। एमएच 05 एसी 555 उनकी पत्नी के स्वामित्व में था।

23. विद्वान वकील ने आगे कहा है कि वर्तमान मामले में भी, एकमात्र प्रतिवादी के वाहनों के विवरण का खुलासा नहीं किया गया है और उसकी भूमि संपत्ति के विवरण का भी खुलासा नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि, इस आधार पर, एकमात्र प्रतिवादी का चुनाव पक्ष में निर्धारित होने के लिए उत्तरदायी है।

24. श्री मंगलम द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि एक उम्मीदवार को अपने 5 साल के आयकर विवरण का विवरण प्रस्तुत करना होगा, लेकिन एकमात्र प्रतिवादी ने केवल एक साल के लिए अपने आयकर विवरण का विवरण दिया है, अर्थात 1918–19। श्री मंगलम ने आगे कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मामले में **पुनरुत्थान भारत बनाम भारत निर्वाचन आयोग और ए. एन. आर, (2014) 14 एस. सी. 189 में** प्रतिवेदित, यह अभिनिर्धारित करते हुए प्रसन्न हुए हैं कि रिक्त विवरणों के साथ शपथ–पत्र भरने से शपथ–पत्र निरर्थक हो जाएगा। वर्तमान मामले में, एकमात्र प्रतिवादी ने 2020 के पटना उच्च न्यायालय ई. पी. संख्या 5 को छोड़ दिया था। ऊपर उल्लिखित कॉलम खाली होने के कारण, उनके चुनाव को निरर्थक घोषित किया जाना चाहिए।

25. दूसरी ओर, एकमात्र प्रतिवादी, श्री अंसुल और श्री माधव राज के लिए शिक्षार्थी वकीलों ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता ने किसी विशेष तथ्य या किसी विशेष सामग्री का संकेत नहीं दिया है, जिसका उल्लेख नामांकन पत्र या फॉर्म–26 में किया जाना बाकी है। नामांकन पत्र दाखिल करते समय एकमात्र प्रतिवादी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं था। यही कारण था कि आपराधिक मामले के कॉलम में 'शून्य' शब्द का उल्लेख किया गया है। जहाँ तक एकमात्र प्रत्यर्थी की संपत्ति और देनदारियों का संबंध है, चुनाव याचिकाकर्ता ने फॉर्म–26 में प्रकट किए जाने के अलावा एकमात्र प्रत्यर्थी की किसी भी संपत्ति से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी। एकमात्र उत्तरदाता द्वारा कुछ भी नहीं दबाया गया था। एकमात्र प्रत्यर्थी के विद्वान वकील श्री माधव राज ने प्रस्तुत किया है कि जहां तक श्री मंगलम का यह निवेदन है कि एकमात्र प्रत्यर्थी का आयकर विवरण पत्र केवल एक वर्ष के लिए फॉर्म–26 में भरा गया है, चुनाव याचिका में इस संबंध में कोई विशिष्ट अभिवचन नहीं है। न ही इस बिंदु पर पक्षों द्वारा साक्ष्य का नेतृत्व किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह तय किया गया कानून है कि कोई भी पक्ष बाद के चरण में एक नया मुद्दा नहीं उठा सकता है, जिसका अनुरोध नहीं किया गया है, और न ही 2020 का पटना उच्च न्यायालय ई. पी. संख्या 5 सबूत उस बिंदु पर दिए गए हैं। हालाँकि, विद्वान वकील ने तर्क के समय, मूल्यांकन वर्षों 2014–15, 2015–16 और 2016–17 के लिए एकमात्र प्रतिवादी के आयकर रिटर्न की ज़ेरॉक्स प्रतियाँ प्रस्तुत की हैं, जिसमें चुनाव याचिकाकर्ता की सकल कुल आय रु, 2,12,420–, रु। 2,68,600–और रु। 4,05,000– क्रमशः। विद्वान अधिवक्ता श्री माधव राज ने प्रस्तुत किया है कि इन निर्धारण वर्षों के लिए आयकर विवरणी में

एकमात्र प्रतिवादी की सकल आय बड़ी राशि की नहीं है और इस जानकारी को न भरने से चुनाव के परिणाम पर भौतिक रूप से प्रभाव नहीं पड़ता। एकमात्र प्रत्यर्थी के विद्वान वकीलों ने आगे प्रस्तुत किया कि **पुनरुत्थान भारत** (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह मानते हुए खुशी हुई है कि गलत या अधूरी जानकारी या भौतिक जानकारी के दमन को केवल तभी ध्यान में रखा जा सकता है, जब यह एक महत्वपूर्ण चरित्र का हो, अन्यथा इसे ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

26. जहां तक ई. वी. एम. के माध्यम से मतों की गिनती के बाद डाक मतपत्रों के माध्यम से मतों की गिनती का संबंध है, एकमात्र प्रतिवादी के विद्वान वकीलों ने प्रस्तुत किया है कि इस संबंध में याचिकाकर्ता का कथन सचाई से बहुत दूर है। याचिकाकर्ता को यह साबित करना होगा कि वोटों की गिनती से पहले 2020 के डाक पटना उच्च न्यायालय ई. पी. संख्या 5 के माध्यम से ई. वी. एम. के माध्यम से वोटों की गिनती की गई थी।

27. विद्वान वकीलों ने आगे कहा है कि **करीम उद्दीन बरबुइया बनाम अमीनुल हक लस्कर का मामला और अन्य (ए. आई. आर. 2024 एस. सी. 2193),** उसमें अपीलार्थी असम विधानसभा के चुनाव में सफल हो गया। उनके चुनाव को इस आधार पर चुनौती देते हुए एक चुनाव याचिका दायर की गई थी कि अपीलार्थी ने अपनी बी. ए. की शैक्षिक योग्यता की झूठी घोषणा की थी, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की शिक्षा योग्यता को दबाया था और बैंक ऋण देय राशि को दबाया था और अनिश्चित भविष्य निधि बकाया को दबाया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन चूक को सारवान प्रकृति का नहीं पाया और अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर लिया गया। **करीम उद्दीन बरबुइया** (ऊपर) के मामले में निर्णय के पैरा–19 और 20 को नीचे निकाला जा रहा हैः .

> *"19. अब, चुनाव याचिका के खाली पढ़ने से, यह सामने आता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आर. पी. अधिनियम की धारा 83 (1) (ए) के तहत बताए जाने की आवश्यकता के अनुसार उसके समर्थन में भौतिक तथ्यों को बताए बिना चुनाव याचिका में केवल गंजे और अस्पष्ट आरोप लगाए हैं। इस तथ्य के अलावा कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यता या 2020 की पटना उच्च न्यायालय ई. पी. संख्या 5 के संबंध में कथित रूप से दिए गए झूठे बयानों और तथ्यों को दबाने और गलत तरीके से प्रस्तुत करने के संबंध में कोई भी आरोप नहीं है। अपनी साझेदारी फर्म के लिए उसके द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में उसकी देयता*

के संबंध में या भविष्य निधि में नियोक्ता के योगदान को जमा करने में उसकी चूक के संबंध में, आर. पी. अधिनियम की धारा 123 (2) में परिकल्पित "अनुचित प्रभाव" की "भ्रष्ट प्रथा" की परिभाषा के भीतर आएगा, चुनाव याचिका में धारा 83 (ए) में विचार किए गए "भौतिक तथ्यों" का संक्षिप्त विवरण भी नहीं है, और आर. पी. अधिनियम की धारा 83 (बी) में विचार किए गए कथित भ्रष्ट व्यवहार के "पूर्ण विवरण" का अभाव है।

20. जहाँ तक "भ्रष्ट आचरण" के आरोपों का संबंध है, प्रत्यर्थी संख्या 1 को भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त बयान देना आवश्यक था कि कैसे अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करके या किसी भी चुनावी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप करने का प्रयास करके अनुचित प्रभाव के "भ्रष्ट अभ्यास" में लिप्त था। बिना किसी आधार के केवल गंजे और अस्पष्ट आरोप चुनाव याचिका में "भौतिक तथ्यों" का संक्षिप्त बयान देने की आवश्यकता का पर्याप्त अनुपालन नहीं होगा। चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा अपनी कार्रवाई का कारण दिखाने के लिए स्थापित मामले के समर्थन में भौतिक तथ्य जो प्राथमिक और बुनियादी तथ्य हैं, उनका अनुरोध किया जाना चाहिए। किसी भी भौतिक तथ्य को छोड़ने से पटना उच्च न्यायालय के 2020 के ई. पी. सं. 5 को कार्रवाई का एक अधूरा कारण माना जाएगा। आर. पी. अधिनियम की धारा 83 (1) (ए) के साथ पठित सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 (ए) के तहत चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए प्रार्थना करने के लिए लौटे उम्मीदवार। उक्त कानूनी स्थिति को इस न्यायालय द्वारा अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी मामले में अच्छी तरह से तय किया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने सामंत एन. बालकृष्ण और एक अन्य बनाम जॉर्ज फर्नांडीज और अन्य और श्री उद्धव सिंह बनाम माधव राव सिंधिया में पहले की घोषणाओं का उल्लेख करने के बाद कहा कि एक भी भौतिक तथ्य को छोड़ने से

> *कार्रवाई का अधूरा कारण बन जाएगा, और यह कि भौतिक तथ्यों के बिना एक चुनाव याचिका बिल्कुल भी चुनाव याचिका नहीं है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि सभी तथ्य जो कार्रवाई के पूर्ण कारण के साथ याचिका को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हैं, उनका अनुरोध किया जाना चाहिए और एक भी भौतिक तथ्य को छोड़ना अधिनियम की धारा 83 (1) (ए) के अधिदेश की अवज्ञा के बराबर होगा और एक चुनाव याचिका को खारिज किया जा सकता है, यदि वह ऐसी किसी बुराई से ग्रस्त है। .*

28. एकमात्र प्रतिवादी के विद्वान वकीलों ने भी ***रवि नम्बूदिरी बनाम के. ए.*** के निर्णय पर भरोसा किया है। ***बैजू और अन्य*** ने ***2022 लाइव लॉ (एससी) 933*** में रिपोर्ट किया, जिसमें केरल पुलिस पटना उच्च न्यायालय ई. पी. संख्या 5 2020 डी. टी. के तहत एक अपराध के लिए अपनी दोषसिद्धि के बारे में नामांकन पत्र में खुलासा करने में एक निर्वाचित उम्मीदवार की विफलता। *धरना* आयोजित करने के लिए अधिनियम, 1960 को उनके चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना गया था।

29. एकमात्र प्रत्यर्थी के विद्वान वकीलों ने आगे प्रस्तुत किया है कि जिस निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ एकमात्र प्रत्यर्थी के नामांकन पत्र को अनुचित रूप से स्वीकार करने का आरोप है, उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है, क्योंकि इस तरह की चुनाव याचिका आवश्यक दलों के गैर–प्रतिवादी के दोष से ग्रस्त है और केवल इसी आधार पर, चुनाव याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।

30. मैंने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया है और पक्षों की ओर से प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचारपूर्वक विचार किया है।

31. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, **संघ के मामले में इंडिया वर्सेज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और एक अन्य, जिसकी रिपोर्ट** (2002) **5 एस. सी. सी. 295** में दी गई थी, ने दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें आवश्यक था चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय कुछ सूचनाओं का प्रकटीकरण। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा–निर्देश उक्त निर्णय के पैरा–48 में विस्तृत हैं। पैरा–48 को नीचे निकाला जा रहा हैः .

> *" निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया जाता है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव की मांग करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार से भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए*

आवश्यक आदेश जारी करके शपथ पत्र पर जानकारी मांगे। उनके नामांकन पत्र का आवश्यक भाग, उसमें प्रस्तुत करते हुए, उनकी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित पहलुओं पर जानकारीः

(1) चाहे उम्मीदवार को अतीत में किसी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो/बरी किया गया हो/आरोपमुक्त किया गया हो–यदि कोई हो, चाहे उसे कारावास या जुर्माने की सजा दी गई हो। (2) नामांकन दाखिल करने के छह महीने से पहले, क्या उम्मीदवार किसी लंबित मामले में आरोपी है, दो साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध का, और जिसमें आरोप बनाया जाता है या न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाता है, यदि हां, तो उसका विवरण।

(3) एक उम्मीदवार और उसके जीवनसाथी और आश्रितों की संपत्ति (अचल, चल, बैंक शेष, आदि)। (4) देनदारियाँ, यदि कोई हों, विशेष रूप से चाहे किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकारी बकाया का कोई अतिदेय हो।

(5) उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता। .

32. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपने नामांकन पत्र में उस निर्णय के पैरा–48 के खंड 1 से 5 में उल्लिखित विवरणों का खुलासा करना होता है। उस आदेश के अनुसरण में, भारत के चुनाव आयोग ने 28–06–2002 पर कुछ निर्देश जारी किए, जिसके अनुसार एक उम्मीदवार को अनुच्छेद संख्या 48 के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के संबंध में एक हलफनामे के रूप में पूरी और पूरी जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। ***भारत संघ बनाम*** **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अन्र** (ऊपर) **पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.)** (ऊपर) के मामले में निर्णय का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त निर्णय की पुष्टि की, लेकिन यह भी माना कि नामांकन की जांच के समय संक्षिप्त जांच के

माध्यम से गलत जानकारी देने के लिए नामांकन पत्र को अस्वीकार करने का निर्देश उचित नहीं हो सकता है। भारत के चुनाव आयोग ने फिर से 2–6–2004 को एक पत्र जारी कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि किसी उम्मीदवार द्वारा गलत जानकारी देने के संबंध में कोई शिकायत किसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो इसे कुछ दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

33. अधिनियम, 1951 में धारा 33–ए को शामिल करने के बाद, संघ के निर्णय में आवश्यक जानकारी **भारत बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड ए. एन. आर.** (ऊपर), एक उम्मीदवार को फॉर्म–26 में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उन सूचनाओं का वर्णन किया गया है, जैसा कि उपरोक्त मामले के पैरा–48 में आवश्यक है।

34. 'अधिनियम, 1951' की धारा 100 चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए आधार प्रदान करती है। किसी उम्मीदवार के चुनाव को केवल 'अधिनियम, 1951' की धारा 100 के तहत गिने गए आधारों पर ही अमान्य घोषित किया जा सकता है। निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र की अनुचित स्वीकृति 2020 के पटना उच्च न्यायालय ई. पी. संख्या 5 के लिए एक आधार है। चुनाव को अमान्य घोषित करना। यदि निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्र को अनुचित तरीके से स्वीकार करता है, तो लौटने वाले उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित किया जा सकता है, लेकिन धारा 100 (1) (डी) (आई) के खाली अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि नामांकन पत्र की अनुचित स्वीकृति के आधार पर चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए, नामांकन पत्र की अनुचित स्वीकृति के कारण लौटने वाले उम्मीदवार के चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ होगा।

'अधिनियम, 1951' की धारा 100 (1) को नीचे निकाला जा रहा है: .

> *"**100. चुनाव घोषित करने के लिए आधार** शून्य। – (1) उप–धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, यदि [उच्च न्यायालय] की राय है कि (क) अपने चुनाव की तारीख को एक लौटाया गया उम्मीदवार संविधान या इस अधिनियम 23 या केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 के तहत सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए योग्य नहीं था, या अयोग्य था; या*

है।

(ख) कि कोई भी भ्रष्ट आचरण एक लौटे उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एक लौटे उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से किया गया है; या

(ग) कि किसी भी नामांकन को अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है; या 2020 का पटना उच्च न्यायालय ई. पी. सं. 5 दिनांक।

(घ) कि चुनाव का परिणाम, जहाँ तक एक लौटे हुए उम्मीदवार की बात है, भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है

(i) किसी भी नामांकन की अनुचित स्वीकृति द्वारा, या

(ख) निर्वाचित उम्मीदवार के हित में किए गए किसी भी भ्रष्ट आचरण द्वारा (उसके चुनाव एजेंट के अलावा किसी अन्य एजेंट द्वारा), या

(ग) किसी भी मत का अनुचित स्वागत, अस्वीकार या अस्वीकृति या किसी भी मत का स्वागत जो शून्य है, या

(iv) संविधान या इस अधिनियम के प्रावधानों या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश का पालन न करने पर, [उच्च न्यायालय] वापस लौटे उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित करेगा।

35. धारा 100 (1) (डी) (आई) के खाली अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वापस लौटे उम्मीदवार के किसी भी चुनाव को केवल नामांकन पत्रों की अनुचित स्वीकृति से अलग नहीं किया जा सकता है या अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता है कि अनुचित स्वीकृति के कारण, वापस लौटे उम्मीदवार के चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है।

36. तत्काल मामले में, चुनाव याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि एकमात्र प्रतिवादी ने अपने नामांकन पत्र के भाग–3 के कॉलम के साथ–साथ कॉलम संख्या को भी खाली छोड़ दिया है। उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में हलफनामे के 5. चुनाव याचिकाकर्ता ने एकमात्र प्रतिवादी के खिलाफ किसी भी आपराधिक मामले का खुलासा नहीं किया। एकमात्र प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नामांकन पत्र भरने के समय उनके खिलाफ कोई मामला नहीं था और यही कारण था कि उन्होंने कॉलम संख्या में 'शून्य' का उल्लेख किया था। 5 उनके शपथ पत्र से। जहां तक चुनाव याचिका में लगाए गए दूसरे आरोप/दावे का संबंध है कि एकमात्र प्रतिवादी ने अपने दो बेटों के पैन का खुलासा नहीं किया, उनके दो नाबालिग बेटों को पैन आवंटित नहीं किया गया था और यही कारण था कि उन्होंने अपने दो नाबालिग बेटों के पैन का खुलासा नहीं किया था। एकमात्र प्रतिवादी ने अपने हलफनामे में उन सभी चार चार पहिया वाहनों के पंजीकरण संख्या का वर्णन किया है, जो उसके पास नामांकन पत्र दाखिल करने के समय थे। चुनाव याचिकाकर्ता एकमात्र प्रतिवादी द्वारा बताए गए चार पहिया वाहनों के अलावा किसी अन्य चार पहिया वाहन का खुलासा नहीं कर सका। वाहनों के निर्माण, मूल्य और खरीद के वर्ष का खुलासा न करने को महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है, जिसके आधार पर एकमात्र प्रतिवादी के चुनाव को अलग रखा जाना चाहिए। चुनाव याचिकाकर्ता उस संपत्ति के अलावा किसी अन्य संपत्ति का संकेत देने में विफल रहा जिसका खुलासा एकमात्र प्रतिवादी ने अपने फॉर्म–26 में किया है। इस प्रकार, चुनाव याचिकाकर्ता कोई भी ऐसी सामग्री जानकारी सामने लाने में विफल रहा जिसका नामांकन पत्रों या एकमात्र प्रतिवादी के फॉर्म–26 में उल्लेख किया जाना बाकी था। केवल इसलिए कि नामांकन पत्र भरने या प्रपत्र–26 में शपथ पत्र प्रस्तुत करने में चूक की गई थी, चुनाव को अमान्य नहीं बना सकते क्योंकि उन चूक को प्रकृति में पर्याप्त नहीं माना जा सकता है, जिसने वापस आए उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया हो सकता है। **मीरेम्बम पृथ्वीराज** (उपरोक्त) के मामले में निर्वाचित उम्मीदवार ने मैसूर विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री का गलत उल्लेख किया था, जो वास्तव में उनके पास नहीं थी और यही कारण था कि उनके चुनाव को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। इसी तरह, **किसान शंकर कथोर** (ऊपर) के मामले में लौटाया गया उम्मीदवार ने अपना बंगला संख्या 866 के साथ–साथ अपनी पत्नी के नाम पर एक वाहन भी छिपा रखा है। वर्तमान मामले में, एकमात्र प्रतिवादी द्वारा कुछ भी नहीं छिपाया गया है।

37. **रिसर्जेंस इंडिया** (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल इसलिए कि कोई जानकारी बची हुई है या अधूरी है, इसका दमन तब तक सामग्री नहीं है जब तक कि यह पर्याप्त चरित्र का नहीं पाया जाता है। उक्त निर्णय का पैरा–3 नीचे दिया गया हैः .

> *"उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, चुनाव आयोग ने दिनांक 1–2002 के आदेश के माध्यम से उम्मीदवारों को एक शपथ पत्र के रूप में पूरी और पूरी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कुछ निर्देश जारी किए, जो विधिवत प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, पटना उच्च न्यायालय ई. पी. के समक्ष शपथ ली। लोकतांत्रिक सुधारों के लिए संगठन में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में। यह भी निर्देश दिया गया कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा हलफनामा प्रस्तुत न करने या कोई गलत या अधूरी जानकारी देने या किसी भी भौतिक जानकारी को दबाने के परिणामस्वरूप नामांकन पत्र को अस्वीकार कर दिया जाएगा, इसके अलावा दंड संहिता, 1860 के तहत दंडात्मक परिणाम आमंत्रित किए जाएंगे। यह और स्पष्ट किया गया कि केवल ऐसी जानकारी को गलत या अपूर्ण या भौतिक जानकारी का दमन माना जाएगा जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की जांच के समय उनके द्वारा की गई संक्षिप्त जांच में पर्याप्त चरित्र का दोष पाया जाता है। .*

38. तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता किसी भी विशिष्ट और भौतिक बात को सामने लाने में विफल रहा है जिसे एकमात्र प्रतिवादी ने अपने नामांकन पत्र में दबा दिया था। केवल इसलिए कि नामांकन पत्र में कुछ आयोग/अनियमितताएं पाई गई हैं, लौटने वाले उम्मीदवार के चुनाव को इस आधार पर अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि चुनाव याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहा है कि चूक/अनियमितताओं ने लौटने वाले उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम को काफी प्रभावित किया है। 39. एकमात्र प्रत्यर्थी के विद्वान वकीलों ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान चुनाव याचिका 2020 के पटना उच्च न्यायालय ई. पी. संख्या 5 से ग्रस्त है। आवश्यक पक्ष के गैर–युग्मक का दोष। निर्वाचन अधिकारी, जिसके खिलाफ नामांकन पत्र को अनुचित तरीके से स्वीकार करने का आरोप है, एक आवश्यक पक्ष है। चुनाव याचिकाकर्ता ने अपनी चुनाव याचिका में निर्वाचन अधिकारी को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया, जिसके कारण चुनाव याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

40. एकमात्र प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकीलों का यह प्रस्तुतिकरण स्वीकार्य नहीं है। 'अधिनियम, 1951' की धारा 82 में यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव याचिका में किसको प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाएगा। 'अधिनियम, 1951' की धारा 82 के नंगे अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यदि चुनाव याचिकाकर्ता, लौटने वाले उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए प्रार्थना करने के अलावा, एक और घोषणा का दावा करता है कि उसे (चुनाव याचिकाकर्ता) निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए, तो उस स्थिति में सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आवश्यक दल हैं। यदि चुनाव याचिकाकर्ता लौटने वाले उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए एक साधारण प्रार्थना करता है और वह खुद को निर्वाचित उम्मीदवार घोषित करने के लिए राहत का दावा नहीं करता है, तो उस स्थिति में लौटने वाले उम्मीदवार आवश्यक पक्ष हैं।

41. यह तय किया गया है कि चुनाव याचिका के माध्यम से चुनाव को चुनौती देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है और जब क़ानून स्वयं इस बारे में विशिष्ट प्रावधान करता है कि 2020 का पटना उच्च न्यायालय ई. पी. संख्या 5 कौन करेगा। पार्टी के रूप में शामिल होने पर, वैधानिक अनिवार्य पार्टी के अलावा किसी और को चुनाव याचिका में आवश्यक पार्टी नहीं माना जा सकता है। अतः एकमात्र प्रत्यर्थी की इस प्रस्तुति को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

42. चुनाव याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि 'नियम, 1961' के नियम 54-ए के अनुसार, निर्वाचन अधिकारी को पहले डाक मतपत्रों से निपटना होता है और उसके बाद ई. वी. एम. द्वारा डाले गए मतों की गिनती की जा सकती है, लेकिन वर्तमान मामले में, सबसे पहले, ई. वी. एम. के माध्यम से डाले गए मतों की गिनती की गई और उसके बाद डाक मतपत्रों की गिनती की गई। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि चुनाव का परिणाम अंततः प्रपत्र-20 में प्रकाशित किया जाता है और जहां तक वर्तमान चुनाव की अंतिम परिणाम-पत्रक का संबंध है, डाक मतपत्रों के माध्यम से गिने गए मतों को ई. वी. एम. के माध्यम से डाले गए मतों के बाद प्रपत्र-20 में दिखाया गया था।

43. मेरे विचार में, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील का प्रस्तुत करना गलत है। चुनाव याचिकाकर्ता (पीडब्लू. 1) ने अपने बयान के दौरान कहा है कि उन्हें वोटों की गिनती में लगे एक अधिकारी से पता चला कि डाक मतपत्रों की गिनती ई. वी. एम. के माध्यम से डाले गए वोटों की गिनती के बाद की गई थी। चुनाव याचिकाकर्ता ने उस अधिकारी के नाम और पदनाम का खुलासा नहीं किया जिसने उसके सामने 2020 की पटना उच्च न्यायालय ई. पी. संख्या 5 का खुलासा किया था। कि डाक मतपत्रों की गिनती ई. वी. एम. के माध्यम से डाले गए मतों के बाद की गई थी। चुनाव याचिकाकर्ता ने मुकदमे के दौरान उस अधिकारी से पूछताछ करने का प्रयास भी नहीं किया।

44. प्रपत्र–20 (अंतिम परिणाम–पत्रक) में दर्ज प्रविष्टियों की श्रृंखला से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि डाक मतपत्रों की गिनती ई. वी. एम. के माध्यम से मतों की गिनती के बाद की गई थी। प्रपत्र–20 में प्रविष्टियाँ करने से पहले, मतों की गिनती पूरी हो जाती है और मतों की गिनती पूरी होने के बाद ही प्रपत्र–20 भरा जाता है। इस संबंध में, 'द रूज़, 1961' का नियम 56 (7) (बी) स्पष्ट है।

'द रूज़, 1961' का नियम 56 (7) नीचे दिया गया हैः .

> *"56(7) एक मतदान केंद्र पर उपयोग किए गए सभी मतपत्रों में निहित सभी मतपत्रों की गिनती पूरी होने के बाद,*
> *(ए) गणना पर्यवेक्षक फॉर्म 16 में गणना के परिणाम के भाग II को भरेगा और हस्ताक्षर करेगा, जिस पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे; और*
> *ख) निर्वाचन अधिकारी प्रपत्र 20 में परिणाम पत्रक में प्रविष्टियाँ करेगा और विवरणों की घोषणा करेगा। .*

45. 'नियम, 1961' के नियम 56 (7) (बी) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मतों की गिनती के बाद प्रपत्र–20 भरा जाता है। इसके अलावा, फॉर्म–20 का प्रारूप 'नियम, 1961' के आधार पर दिया गया है और प्रारूप के खाली अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मतदान केंद्र पर दर्ज मतों का कॉलम डाक मतपत्रों पर दर्ज मतों से पहले दिया गया है। इस प्रकार, प्रपत्र–20 के प्रारूप के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि सबसे पहले ई. वी. एम. के माध्यम से डाले गए मतों की प्रविष्टियों की पंक्ति प्रपत्र–20 में मुद्रित की गई है और उसके बाद डाक मतपत्रों पर दर्ज मत उस रूप में मुद्रित किए गए हैं। इस प्रकार, चुनाव याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि डाक मतपत्रों की गिनती ई. वी. एम. के माध्यम से डाले गए मतों की गिनती के बाद की गई थी।

46. उपर्युक्त टिप्पणियों के आधार पर, दोनों मुद्दों का निर्णय नकारात्मक रूप से किया जाता है।

47. नतीजतन, चुनाव याचिका खारिज कर दी जाती है।

(नवनीत कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

एचआर/–

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वियन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।